मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने रविवार को नई दिल्ली के जोधपुर हाउस में ''एक पेड़ मां के नाम'' अभियान के तहत बिल्व का पौधा लगाया। इस अवसर पर उन्होंने कहा जैव विविधता को ध्यान में रखते हुए विभिन्न प्रजातियों के पौधे लगाने चाहिए।

श्रीनगर हवाई अड्डे पर सेना के अधिकारी व एयरलाइन कर्मचारियों में मारपीट

स्पाइसजेट के प्रवक्ता ने आरोप लगाया कि एक कर्मचारी की रीढ़ की हड्डी टूट गई

- एयर लाइन्स के अनुसार, सेना अधिकारी के सामान का वजन अधिक था तथा उनसे बोर्डिंग गेट पर अतिरिक्त भार के भुगतान के लिए कहा गया था।
- सेना ने कहा कि वह जाँच में पूरा सहयोग करेगी।

श्रीनगर, 3 अगस्त। श्रीनगर में हवाई अड्डे पर सेना के एक वरिष्ठ अधिकारी द्वारा एक निजी एयरलाइंस के चार कर्मचारियों को कथित तौर पर बुरी तरह पीटने की घटना के प्रकाश में आने के बाद एयरलाइंस ने नागरिक उड्डयन मंत्रालय को पत्र लिखकर मामले में उचित कार्रवाई करने का अनुरोध किया है।

एयरलाइंस स्पाइसजेट के प्रवक्ता ने बताया कि कश्मीर में तैनात एक वरिष्ठ सेना अधिकारी ने 26 जुलाई को श्रीनगर हवाई अड्डे पर उसके चार कर्मचारियों पर कथित तौर पर तब हमला बोल दिया जब उन्होंने सामान के किराए के भुगतान का अनुरोध किया। इस मामले की प्राथमिकी थाने में दर्ज कराई है और नागरिक उड्डयन नियमों के अनुसार यात्री का नाम काली सूची (नो-फ्लाई) में डालने की प्रक्रिया शुरू हो गई है।

एयरलाइंस ने कहा कि उसने घटना का सीसीटीवी फुटेज हासिल करके पुलिस को सौंप दिया है और वह इस मामले की पूरी कानूनी और नियामकीय जाँच पर जोर देगी।

प्रवक्ता ने बताया कि उक्त अधिकारी ने श्रीनगर से दिल्ली जाने वाली उड़ान संख्या एसजी-386 के बोर्डिंग गेट पर तैनात एयरलाइंस के चार कर्मचारियों को इतना पीटा कि एक कर्मचारी की रीढ़ की हड्डी टूट गई और उसके जबड़े में गंभीर चोटें आईं। जब दूसरे कर्मचारी उसे बचाने आए तो अधिकारी ने उन्हें भी पीटा।

प्रवक्ता ने कहा कि अधिकारी के सामान का वजन 10 किलोग्राम था जबकि, मुसाफिरों को विमान के अदंर केवल सात किलोग्राम ले जाने की इजाजत है।

प्रवक्ता ने कहा, ''जब उनको विनम्रतापूर्वक इस बारे में बताया गया और लागू शुल्क का भुगतान के लिए कहा गया, तो यात्री ने इन्कार कर दिया और बोर्डिंग प्रक्रिया पूरी किए बिना ही जबरन एयरोब्रिज में प्रवेश कर गया। यह विमानन सुरक्षा प्रोटोकॉल का स्पष्ट उल्लंघन था।''

प्रवक्ता ने कहा, ''सीआईएसएफ के एक अधिकारी ने उसे वापस गेट तक पहुँचाया।''

इस मामले में सेना ने कहा है कि वह जांच में पूरा सहयोग करेगी। सेना ने बयान में कहा, हम अनुशासन के उच्च मानकों पर चलते हैं और इस घटना को गंभीरता से ले रहे हैं।

मुख्यमंत्री भजनलाल ने जोधपुर हाउस में बिल्व का पौधा लगाया

दिल्ली में पत्रकारों से वार्ता में उन्होंने रिफाइनरी के काम में तेजी लाने की बात कही

- मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में धार्मिक पर्यटन तथा विरासत से जुड़े पर्यटन स्थलों को बढ़ावा दिया जायेगा। प्राचीन हवेलियों और हेरिटेज सम्पत्तियों की सूची बनवाई गई है तथा उनके उचित रखरखाव के लिए सरकार हर संभव सहयोग करेगी।

नई दिल्ली/जयपुर, 3 अगस्त। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने रविवार को नई दिल्ली के जोधपुर हाउस में 'एक पेड़ मां के नाम' अभियान के तहत बिल्व का पौधरोपण किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि बिल्व जैसे पौधे धार्मिक और औषधीय दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। जैव विविधता को ध्यान में रखते हुए विभिन्न प्रजातियों के पौधे लगाने चाहिए।

शर्मा ने रविवार को नई दिल्ली के बीकानेर हाउस में पत्रकारों के साथ बातचीत में कहा कि हमारी सरकार राजस्थान के चहुंमुखी विकास के लिए कार्य कर रही है। राजस्थान रिफाइनरी के काम में तीव्रता लाकर यहां बनने वाले बाय-प्रोडक्ट्स को संसाधित करके इससे जुड़े उद्योगों की स्थापना पर केंद्र सरकार के साथ मिलकर काम किया जा रहा है।

मुख्यमंत्री ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा कि प्रदेश में विभिन्न प्रकार के पर्यटन को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिसमें विशेष रूप से धार्मिक पर्यटन और हमारी विरासत से जुड़े पर्यटन स्थल शामिल हैं। उन्होंने कहा कि प्राचीन हवेलियों और हेरिटेज संपत्तियों की सूची बनवाई गई है। इनके उचित रखरखाव के लिए सरकार हर संभव सहयोग करेगी।

रीट पेपर लीक में जब्त 1.20 करोड़ की एफडी होगी

यह राशि गत चार साल से गंगापुर सिटी थाने में रखी हुई थी

जयपुर, 3 अगस्त। राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा 2021 पेपरलीक मामले में जब्त 1.20 करोड़ रुपए से अधिक राशि की एफडी होगी।

ईडी मामलों की विशेष अदालत ने एसओजी को इसके निर्देश दिए हैं। यह राशि पिछले चार साल से गंगापुरसिटी थाने में रखी थी, लेकिन अब पेपरलीक का मामला जयपुर ट्रांसफर होने के बाद जब्त कैश और अन्य माल ईडी कोर्ट को भेज दिया गया।

यह राशि गंगापुरसिटी थाना पुलिस ने साल 2021-22 में अलग-अलग आरोपियों से बरामद की थी।

मामले में विशिष्ठ लोक अभियोजक बीएस चौहान ने बताया कि गंगापुर सिटी थानाधिकारी की ओर से प्रार्थना पत्र पेश करके जब्तशुदा एक करोड़ 20 लाख दो हजार रुपए व सामान को न्यायालय में जमा करवाने का आग्रह किया गया। कोर्ट ने प्रार्थना पत्र को निस्तारित कर नकदी को एफडी में जमा करवाने का आदेश दिया, वहीं जब्तशुदा सामान एसओजी थाने को सौंप दिया।

कोर्ट ने कहा कि एफडी अधिक ब्याज देने वाले बैंक में करवाई जाए और बैंक का नाम विशिष्ट लोक अभियोजक को बताया जाए।

सुनवाई के दौरान रीट पेपरलीक मामले के आरोपी चन्दनराम, कमला विश्नोई, सुमन, सोहिनी महेन्द्र कुमार, सुरेन्द्र सिंह, राजेश कुमार मीना, संजय कुमार मीना बत्ती लाल मीणा, रवि मीणा, अमित कुमार मीणा, कमलेश मीणा, शिवदान मीना, नरेन्द्र विश्नोई, मुन्नीलाल विश्नोई व अशोक कुमार मौजूद रहे, जबकि शेष आरोपियों का हाजिरी माफी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर लिया। अब 11 अगस्त को मामले की सुनवाई करेगी।

बद्रीनाथ हाईवे पर पुल क्षतिग्रस्त, भारी वाहनों पर रोक

- हल्के वाहनों का आवागमन चालू रखा गया है तथा बद्रीनाथ यात्रा भी फिलहाल जारी है।

चमोली, 03 अगस्त। उत्तराखण्ड के चमोली जिले मे शनिवार रात्रि को भारी वर्षा होने के कारण बदरीनाथ हाईवे पर हनुमान चट्टी स्थित मोटर पुल के दोनों ओर की एबटमेंट सुरक्षा दीवार क्षतिग्रस्त हो गयी है। सतर्कता और सुरक्षा को देखते हुए फिलहाल भारी वाहनों के आवागमन पर रोक लगाई गई है। छोटे वाहनों टैक्सी, कार सहित अन्य हल्के वाहनों के आवागमन पर कोई रोक नहीं लगाई गई है। बदरीनाथ यात्रा फिलहाल जारी है।

पुलिस अधीक्षक कार्यालय ने जानकारी देते हुए रविवार को बताया फिलहाल बदरीनाथ हाईवे यहाँ पर हल्के वाहनों के ही खोला गया है। पांडुकेश्वर से ऊपर सभी भारी वाहनों को प्रतिबंधित किया गया है।

गडकरी के घर ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

पुलिस और डॉग स्कॉयड की टीम ने गडकरी के घर मेंसर्च ऑपरेशन भी चलाया।

कुछ घंटों बाद गडकरी के घर को बम से उड़ाने की धमकी देने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपी का नाम उमेश विष्णु राउत है। उमेश विष्णु राउत मेडिकल चौक स्थित एक देसी शराब की दुकान पर काम करता है। पुलिस ने उसे नागपुर के बीमा दवाखाना के पास से गिरफ्तार किया है।

बता दें कि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी नागपुर में ही मौजूद हैं। पुलिस की टीम अब गिरफ्तार आरोपी से पूछताछ कर धमकी देने के पीछे की मंशा को जानना चाहेगी कि कहीं इस घटना में कोई और एंगल तो नहीं है।

सरकार ने 35 ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

अधिक वसूली गई राशि को वसूलना शामिल होगा। एनपीपीए ने साफ किया है कि निर्धारित मूल्यों में वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) शामिल नहीं है, जिसे लागू होने पर जोड़ा जा सकता है।

निर्माताओं को सभी वैधानिक आवश्यकताओं का पालन करना होगा, इंटीग्रेटेड फार्मास्युटिकल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के माध्यम से फॉर्म वी में अपडेटेड प्राइस लिस्ट जारी करनी होगी और एनपीपीए तथा राज्य औषधि नियंत्रकों को जानकारी देनी होगी। स्पेसिफाइड फॉर्मूलेशन और निर्माताओं के लिए जारी किए गए किसी भी पूर्व मूल्य आदेश को इस लेटेस्ट नोटिफिकेशन द्वारा निरस्त कर दिया गया है।

सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को भूपेश बघेल की अग्रिम जमानत पर सुनवाई की संभावना

छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री ने आशंका जताई है कि राजनीतिक प्रतिशोध के तहत उनकी गिरफ्तारी की जा सकती है

- शराब, कोयला तथा महादेव सट्टा घोटाले में सीबीआई और ईडी की जाँच के बाद उनके पुत्र चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी हो चुकी है। राज्य व केन्द्र की जाँच एजेन्सियों ने कुछ समय पूर्व संबंधित मामलों की जाँच की गति तेज कर दी है।

रायपुर, 03 अगस्त। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव तथा पंजाब प्रभारी भूपेश बघेल को आशंका है कि उन्हें शराब,कोयला और महादेव सट्टा एप घोटालों में नाम आने के बाद कभी भी गिरफ्तार किया जा सकता है।

इस गिरफ्तारी से बचने के लिए बघेल ने सर्वोच्च न्यायालय में अग्रिम जमानत याचिका लगाई है और न्यायालय सोमवार को उनकी याचिका पर सुनवाई के लिए विचार कर सकता है।

बघेल ने याचिका में मांग की है कि उन्हें इन मामलों में किसी भी तरह से गिरफ्तार न किया जाए और जांच में सहयोग करने का अवसर दिया जाए। याचिका में यह भी उल्लेख किया है कि जिस तरह उनके बेटे चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी राजनीतिक द्वेष के चलते की गई, उसी तरह उन्हें भी निशाना बनाया जा सकता है।

पूर्व मुख्यमंत्री ने आशंका जताई है कि, राजनीतिक प्रतिशोध के तहत उनकी गिरफ्तारी की जा सकती है। यह याचिका ऐसे समय में दाखिल की गई है जब राज्य और केन्द्र की जांच एजेसिंयों, ईडी तथा आर्थिक अपराध शाखा सहित कई केन्द्रीय जांच एजेंसियों ने संबंधित मामलों की जांच तेज कर दी है।

यह याचिका सोमवार को सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई के लिए लिस्टिंग की गई है। इसके अलावा बघेल और उनके बेटे ने सीबीआई और ईडी द्वारा की जा रही जांचों की वैधता को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी है। याचिका में सवाल उठाया गया है कि सीबीआई और ईडी को छत्तीसगढ़ में जांच करने का अधिकार किस आधार पर मिला, जब राज्य सरकार ने पहले ही उनकी आम सहमति वापस ले ली थी।

सितंबर से ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

12 के अनुसार हर साल रजिस्टर्ड पोस्ट की संख्या में गिरावट आ रही है। साल 2011-12 में रजिस्टर्ड डाक से भेजने वाले आर्टिकल 24 करोड़ से घटकर 2019-20 में 18 करोड़ के रह गए। 25 फीसदी की कमी साफ देखी जा सकती है। कोरोना के बाद से तो स्थिति और खराब हो गई है।

सरयू नहर में ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

आया। बमुश्किल खिड़की का शीशा तोड़कर एक-एक को बाहर निकाला। तब तक सभी की मौत हो चुकी थी।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दुर्घटना का संज्ञान लेकर शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। उन्होंने घायलों के समुचित उपचार के निर्देश दिए हैं। सीएम ने मृतकों के परिजनों को पांच लाख की आर्थिक सहायता दिए जाने के निर्देश दिए हैं।

चुनाव आयोग ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

पत्र नहीं रख सकता है। अगर रखता है तो यह अपराध है। एनडीए के प्रवक्ताओं ने साफ कहा कि चुनाव आयोग को इस पर संज्ञान लेना चाहिए और तत्काल इस मामले को लेकर तेजस्वी यादव पर मुकदमा दायर करना चाहिए।

'साढ़े छः ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

आयोग के कथित कदम का विरोध करते हुए आरोप लगाया था कि यह भाजपा की उन राज्यों की वोट देने वाली आबादी का डेटा बदलने की चाल है जहाँ उसकी कोई पकड़ नहीं है।

ग्रेनाइट खदान ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने इस दुर्घटना पर गहरा दुःख व्यक्त करते हुए अधिकारियों को घायल श्रमिकों को बेहतर चिकित्सा प्रदान करने के निर्देश दिये हैं।

भारत ने अमेरिका से इस वर्ष दोगुनी राशि का तेल खरीदा

- अप्रैल-जून 2024 में आयात 1.73 बिलियन डॉलर था, जो इस अप्रैल-जून में 3.7 बिलियन डॉलर हो गया।

नई दिल्ली, 03 अगस्त। रूस से कच्चा तेल खरीदने पर आपत्ति जताने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति के लिए खुशखबरी है। भारत ने पिछले तीन महीने में पिछले साल की अपेक्षा 114 प्रतिशत ज्यादा कच्चा तेल खरीदा है। अगर जनवरी से 25 जून तक बात करें तो भारत ने पिछले साल की अपेक्षा अमेरिका से 51 प्रतिशत ज्यादा कच्चा तेल खरीदा है। पिछले साल जनवरी से जून तक 0.18 एमबी/डी कच्चा तेल भारत में आयात हुआ था, इस साल अब तक इसकी मात्रा .271 एमबी/डी पहुंच चुकी है। 2024 की तुलना में अप्रैल से जून 2025 तिमाही में भारत ने अमेरिका से 114 प्रतिशत ज्यादा कच्चा तेल आयात किया है। इन आयातों का वित्तीय मूल्य दोगुने से भी अधिक हो गया है। 2024-25 की पहली तिमाही में 1.73 बिलियन डॉलर से बढ़ कर 2025-26 की अप्रैल से जून में 3.7 बिलियन डॉलर हो गया है।

सूत्रों के अनुसार, कच्चे तेल के आयात की गति और तेज होती दिख रही है। गर्मियों के महीनों में भी यह वृद्धि जारी रहने की उम्मीद है। गत जुलाई में भारत ने जून की तुलना में अमेरिका से 23 प्रतिशत ज्यादा कच्चा तेल आयात किया है। भारत के कुल कच्चे तेल आयात में अमेरिका की हिस्सेदारी महज 3 प्रतिशत थी, जो जुलाई में बढ़ कर 8 प्रतिशत हो गई है। सूत्रों का कहना है कि वित्तीय साल 2025-2026 में भारतीय कंपनियां अपने कच्चे तेल के आयात में 150 प्रतिशत की वृद्धि करेंगी। आयात की यह बढ़त केवल कच्चे तेल पर नहीं है। यह बढ़त अन्य इनर्जी प्रोडक्ट पर भी है। अमेरिका से भारत आने वाला तरलीकृत पेट्रोलियम गैस (एलपीजी) और तरलीकृत प्राकृतिक गैस (एलएनजी) का आयात भी तेजी से बढ़ा है। वित्तीय साल 2024-25 में एलएनजी आयात 2.46 अरब डॉलर तक पहुंच गया, जो पिछले वर्ष के 1.41 अरब डॉलर से लगभग दोगुना है। यानी एलएनजी आयात में करीब 100 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

ऊँची लहरों से केरल के तटों पर पानी भरने की आशंका

- मछुआरों व स्थानीय नागरिकों से अत्यधिक सावधानी बरतने व इन क्षेत्रों में जाने से बचने को कहा गया है।

तिरुवनंतपुरम, 03 अगस्त। भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र ने केरल के तटीय इलाकों में ऊंची लहरों के कारण पानी का स्तर बढ़ने की आशंका को देखते हुये चेतावनी जारी की है।

स्थानीय भाषा में इसे कल्लक्कडल के नाम से भी जाना जाता है जो शक्तिशाली समुद्री उफानों के कारण तटीय बाढ़ की घटना को संदर्भित करता है।

यह अक्सर दूर के तूफानों से उत्पन्न होती है। समुद्र में दूर-दूर तक तेज हवाओं या तूफानों के कारण उत्पन्न ये लहरें लंबी दूरी तय करती हैं और तट पर पहुंचकर भारी बाढ़ और क्षति का कारण बन सकती हैं।

कल्लक्कडल एक स्थानीय शब्द है जिसका प्रयोग केरल में, विशेष रूप से मानसून-पूर्व मौसम के दौरान, उफान के कारण आने वाली बाढ़ के लिए किया जाता है।

इन हालात को देखते हुए मछुआरों और तटीय निवासियों को अत्यधिक सावधानी बरतने की सलाह देते हुए कहा गया है कि वे इन क्षेत्रों में जाने से बचें और स्थानीय अधिकारियों के निर्देशों का पालन करें।

'योगी के कैबिनेट मंत्री राजभर बिहार में भाजपा पर दबाव बना रहे हैं'

वे बिहार विधानसभा चुनाव में सम्मानजनक सीटों पर गठबंधन करना चाहते हैं

- राजभर ने कहा कि उनकी पार्टी कई वर्षों से बिहार में सक्रिय है, इसलिए वे विधानसभा चुनाव में अपनी उपस्थिति दर्ज कराना चाहते है।

लखनऊ, 3 अगस्त। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार में कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने अब नए समीकरण के तहत भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) पर दबाव बनाना शुरू कर दिया है। इसके संकेत उस समय मिलने शुरू हो गए जब उन्होंने कहा कि बिहार विधानसभा चुनाव में भाजपा के साथ गठबंधन नहीं हुआ तो सारे विकल्प खुले हुए हैं।

दरअसल, भाजपा की सहयोगी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी ने बिहार चुनाव लड़ने के लिए गैर-भाजपा दलों के साथ तीसरा मोर्चा बनाने के संकेत देकर अपनी राजनीतिक ताकत फिर से दिखानी शुरू कर दी है।

सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी (सुभासपा) प्रमुख ओम प्रकाश राजभर ने अपने बयान में कहा अगर बिहार में भाजपा के साथ हमारा गठबंधन नहीं होता है, तो हम सभी विकल्प खुले रखेंगे।

योगी सरकार में मंत्री राजभर ने कहा कि उनकी पार्टी प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी और मुकेश साहनी की विकासशील इंसान पार्टी (वीआईपी) सहित कई छोटी पार्टियों के साथ बातचीत कर रही है।

राजभर ने कहा कि उनकी पार्टी बिहार की 243 विधानसभा सीटों में से कम से कम 156 पर चुनाव लड़ने की योजना बना रही है। उन्होंने कहा यह सब इस बात पर निर्भर करता है कि स्थिति क्या और कैसी बनती है। हम बिहार में अपनी उपस्थिति दर्ज कराना चाहते हैं, जहां हम पिछले कई वर्षों से सक्रिय हैं।

भाजपा के सूत्रों ने बताया कि राजभर सीवान, चंपारण, सारण, गोपालगंज और बक्सर के कुछ इलाकों में सम्मानजनक सीटों के लिए भाजपा से कड़ी मोलभाव कर रहे हैं जहां राजभर, राजवंशी, राजधोबी और भर समुदायों की अच्छी-खासी मौजूदगी है। पार्टी का लक्ष्य पटवा और मंडल जैसी जातियों को भी एकजुट करना है।

एयर इंडिया का पुनः ''राष्ट्रीयकरण'' ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

- पर, यह भी जरूरी है कि एयर इंडिया का मैनेजमैंट अपनी दिक्कतों व कमियों के बारे में सही जानकारी दे जनता को, नहीं तो यह ''इम्प्रेशन'' जोर पकड़ लेगा कि मैनेजमैंट के पास सिविल एविएशन का पूरा अनुभव नहीं है और कार्य कुशलता के अभाव में कंपनी डूब जायेगी।

विमान ऑर्डर दिया है, तकनीक और कर्मचारियों के प्रशिक्षण में निवेश किया है, और ब्रांड की साख वापस लाने की कोशिश की जा रही है। इस तरह का बदलाव, अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुसार भी, कई सालों में होता है, महीनों में नहीं।

आज जो समस्याएं एयर इंडिया में देखी जा रही हैं, वे पुनर्गठन की प्रक्रिया का हिस्सा हैं, न कि व्यवस्था की विफलता। अभी अगर फिर से इसका राष्ट्रीयकरण किया गया, तो भारत के आर्थिक सुधारों की साख को बड़ा झटका लगेगा और वैश्विक निवेशकों का भरोसा कमजोर होगा, जिन्हें नीति में स्थिरता चाहिए।

यह बात सही है कि एयर इंडिया के साथ भावनात्मक लगाव आज भी बना हुआ है। दशकों तक यह भारत की हवाई पहचान रही है, प्रधानमंत्रियों को ले जाने वाली, संकट में नागरिकों को वापस लाने वाली और प्रवासी भारतीयों को देश से जोड़ने वाली एयरलाइन। जब वही एयरलाइन निजी हाथों में संघर्ष करती दिखती है, तो लोगों को पीड़ा होती है।

अगर टाटा समूह द्वारा दी जा रही पूंजी और स्वतंत्रता के बावजूद एयरलाइन लगातार विफल होती है, तो सार्वजनिक हित की बात फिर से उठ सकती है। मनीष तिवारी की यह चिंता, कि गैर-विमानन पेशेवर (नॉन एविएशन प्रॉफेशनल्स) इसे चला रहे हैं, इस बड़े भय को दर्शाती है कि एयर इंडिया की आत्मा सिर्फ लाभ कमाने के चक्कर में कहीं खो रही है।

इसके अलावा, भारत जैसे विशाल देश में हवाई संपर्क एक रणनीतिक संसाधन है। अगर निजी नियंत्रण में कुछ प्रमुख मार्ग घाटे का सौदा बनते हैं, तो जनता की जरूरतें पूरी नहीं होंगी। ऐसे में सरकार को सीधे या रैग्युलेशन के ज़रिए हस्तक्षेप करना पड़ सकता है।

फिर भी, एयर इंडिया का पुनः राष्ट्रीयकरण अभी जल्दबाज़ी होगी और मुश्किल से हो रहे सुधारों को कमज़ोर करने का खतरा पैदा हो सकता है। एयर इंडिया को कब्ज़े में लेने की नहीं, बल्कि कड़ी निगरानी की ज़रूरत है। सरकार को अपने नियामक अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए सेवा गुणवत्ता, सुरक्षा और प्रतिस्पर्धा पर नज़र रखनी चाहिए। वहीं, टाटा समूह को संवाद बेहतर करना होगा, तेज़ी से कदम उठाने होंगे और यात्रियों व नीति-निर्माताओं, दोनों को यह भरोसा दिलाना होगा कि वे इस जिम्मेदारी के लायक हैं।

निजीकरण कभी कोई जादू की छड़ी नहीं था। यह एक ऐसा कदम था, जिससे सरकार को एयरलाइन चलाने के काम से आज़ाद किया जा सके, ताकि वह शासन पर ध्यान दे सके। इसी भावना में, ज़रूरी है कि जो टूटा है, उसे ठीक किया जाए, बिना उसे फिर से पूरी तरह बिगाड़े।

राष्ट्रदूत (एचयूएफ) के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक सोमेश शर्मा द्वारा मैसर्स अरावली प्रिन्टर्स, राष्ट्रदूत भवन, चुंगी नाका के पास, अजमेर (राजस्थान) से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक-राजेश शर्मा, आर.एन.आई. नं. 65015/96, जयपुर कार्यालयः सुधर्मा एम.आई.रोड, जयपुर। फोनः 2372634, 4103333-34 फैक्स : 0141-2373513, कोटा कार्यालय : पलायथा हाऊस, छत्रपति शिवाजी मार्ग, कोटा। फोनः 2386031, 2386032,फैक्सः0744-2386033, उदयपुर कार्यालयः आयड मैन रोड आयड, उदयपुर। फोनः 2413092, फैक्स : 0294-2410146, बीकानेर कार्यालय : कुम्भाना हाऊस, हनुमान हत्था, बीकानेर। फोनः 2200660, फैक्स 0151-2527371, जालोर कार्यालय :- जी 1/63, इन्डस्ट्रीयल एरिया, फेस प्रथम, जालोर। फोनः 226422, 226423, फैक्सः 02973-226424 हिण्डौनसिटी कार्यालय :- जी -1-201, रीको औद्योगिक क्षेत्र, हिण्डौनसिटी। फोनः 230200, 230400, फैक्सः 07469-230600 चूरू कार्यालय : एच-150, रीको औद्योगिक क्षेत्र, चूरू, फोन : 256906, 256907, फैक्सः 01562-256908